



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, २५ अगस्त, १९९२/३ भाद्रपद, १९१४

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-२, १७ अगस्त, १९९२

सं० पी० सी९ एच०-ए० ए० (५) ५१/८८—क्योंकि उप-मण्डलाधिकारी (ना०) पालमपुर द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार श्री बलदेव सिंह (निलम्बित) प्रधान, ग्राम पंचायत अन्द्रेटा, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ अपने ग्राम सभा क्षेत्र के निवासियों से तीन रुपये प्रति राशन कार्ड की दर से राशि वसूल करते रहे जिसे उन्होंने सभा निधि में जमा नहीं किया और राशन कार्ड एक वर्ष की बजाय ५ वर्षों के लिए जारी करते रहे जो विभागीय आदेशों व पंचायती राज अधिनियमों व उसके अन्तर्गत बने नियमों की उल्लंघना है;

क्योंकि बलदेव सिंह प्रधान (निलम्बित) ग्राम सभा क्षेत्र अन्द्रेटा के वार्ड नं० ४ से पंच पद के लिए भी निर्वाचित हुए थे और नियमानुसार वह केवल एक पद पर ही आसीन रह सकते थे और एक पद त्याग देना उनके लिए अनिवार्य था जो नहीं किया अपितु वार्ड नं० ४ के लिए श्री बखशी चन्द को वार्ड का पंच मनोनीत कर दिया जैसा कि राशन कार्डों पर छपे पंच के नाम से स्वतः स्पष्ट है;

क्योंकि श्री बलदेव सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत अन्द्रेटा अनुचित रूप से अपने सभा क्षेत्र में लोगों से स्थानीय खड्डों के रेत, बजरी, पत्थरों का अधिकार शुल्क (रायल्टी) अनाधिकृत रूप से बसूल कर रहे हैं;

क्योंकि उक्त कृत्य के लिए श्री बलदेव सिंह प्रधान को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत और पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन उपायुक्त कांगड़ा द्वारा दिनांक 10 जून, 1992 को 7 दिन का निलम्बनाय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 20 जून, 1992 को निलम्बित कर दिया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोकि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के तहत प्राप्त हैं निम्नलिखित आदेशित करते हैं :—

(क) उपायुक्त कांगड़ा के कार्यालय आदेश सं० पंच के० जी० आर० आई० (12) 2/91-794-801 दिनांक 20 जून, 1992 द्वारा पारित निलम्बन आदेश रद्द किया जाता है क्योंकि प्रधान द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस के उत्तर जोकि 15-6-92 को उनके कार्यालय में प्राप्त हो चुका था को समय पर प्रस्तुत करके जल्दबाजी में निलम्बित किया गया है।

(ख) उपर्युक्त वर्णित दोषों में वास्तविकता को जानने के लिए अतिरिक्त दण्डाधिकारी कांगड़ा को जांच अधिकारी तथा जिला अंशेक्षण अधिकारी कांगड़ा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से शीघ्र अति शीघ्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षरित/-  
अतिरिक्त सचिव (पंचायत)।